an>

Title: Need to provide subsidy for natural fertilizers.

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : कैमिकल फर्टिलाइजर अर्थात् यूरिया और पेस्टीसाईड्स एंड कैमिकल पर सब्सिडी हेतु पिछले 3 वर्षों में कुल यूरिया पर 168788.04 करोड़ रूपये की सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को जारी की गई जिसमें 66270.27 करोड़ रूपये आयातित कंपनी तथा 102517.77 करोड़ रूपये स्वदेशी यूरिया कंपनियों को दिए गए हैं। इसी प्रकार आयातित पेस्टीसाईड्स एंड कैमिकल हेतु 52780.87 करोड़ रूपये विदेशी तथा 63355.65 करोड़ रूपये स्वदेशी पेस्टीसाईड्स एंड कैमिकल कंपनियों को सब्सिडी के रूप में जारी किए गए हैं।

मैं कहना चाहता हूँ कि कैमिकल फर्टिलाइजर के रूप में तो सब्सिडी जारी की जाती है लेकिन प्राकृतिक उर्वरकों पर किसी प्रकार की कोई सब्सिडी जारी नहीं की जाती है जिसके चलते किसान जैविक खेती की ओर आकर्षित नहीं होते।

रासायनिक खाद का प्रयोग पारंपरिक प्राकृतिक खाद्य के तरीके की जड़ से खत्म करता जा रहा है। रसायनों के प्रभाव से जमीन भी धीरे-धीरे बंजर होने लगती है और कीड़ों के अधिक पनपने की संभावना बनी रहती है जिससे बचने के लिए किसान अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करने लगते हैं। कुछ कीटनाशक तो सिस्टमेटिक होते हैं जो पानी या खाद के साथ घोलकर प्रयोग में लिए जाते हैं जिसका असर प्लांट के अंदर और उपज के अंदर तक हो जाता है। ये कीटनाशक ऊपर से प्रे किए जाने वाले कीटनाशकों से कहीं अधिक हानिकारक होते हैं। ऐसे कीटनाशक मानव शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या से किसान को निजात दिलाने के लिए हाल ही में राजस्थान में "भूमि स्वास्थ्य कार्ड स्कीम" जारी की है जो अपने आप में पहला निर्णय है जिससे किसानों को अपनी जमीन में रसायनिक खाद के प्रयोग की जानकारी मिल सकेगी और किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकेगा। इसके साथ-साथ आमजन को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा सकेगी। किसान चाहते हुए भी जैविक खाद और प्रे का प्रयोग नहीं कर पा रहा क्योंकि ये कैमिकल खाद व प्रे से अधिक महंगे हैं। जैविक खाद पर सब्सिडी नहीं दी गई तो हम चाहते हुए भी जैविक खेती को प्रोत्साहन नहीं दे पाएंगे।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खाद को सब्सिडी देने की कृपा की जाए।